

आयोजनागत

संख्या- 478 / 111 (3) / 09-07(सामान्य) / 2009

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-3

देहरादून, दिनांक ⁰⁴ अक्टूबर, 2009

विषय:- वित्तीय वर्ष 2009-2010 में लोक निर्माण विभाग हेतु आय-व्ययक में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2642/32 बजट (सा0)/09-10 दि0 31.7.2009 के सन्दर्भ में तथा शारानादेश संख्या- 281 / 111(3) / 09-07(सामान्य) / 2009, दिनांक 08 जून, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2009-10 के अनुदान संख्या-22 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित सलग विवरणानुसार केन्द्र पोषित योजनाओं हेतु रु0 580.00 लाख (रु0 पांच करोड़ अरसी लाख मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वहन पर रखे जाने की निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :

1 वितरण अधिकारी के द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0-8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय-13 के प्रस्तर-116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर 128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी (मुख्य अभियन्ता, लो0नि.वि0) द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और यदि नियमित रूप से सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्य मंत्री जी/मुख्य सचिव) कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर 130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

2 प्लान पक्ष की उक्त योजनाओं की सी0सी0एल0प्रत्येक त्रैमास में समय से निर्गत कर उसकी प्रति प्रत्येक त्रैमास में शासन को भी प्रेषित की जायेगी। विभागाध्यक्ष पर दायित्व होगा कि प्रत्येक खण्ड से समय से योजनाओं का विवरण प्राप्त करके समय से उसकी खाख सीमा निर्गत करायें ताकि स्वीकृत की जा रही धनराशि का समय से उपयोग हो सके और योजना का लाभ जनता को प्राप्त हो सके। जिस उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा विलम्ब से विभागाध्यक्ष को योजनाओं का विवरण सूचित करने के कारण सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसका स्पष्टीकरण प्राप्त कर उस कारण न होने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी और लगातार दो बार योजनाओं का विवरण समय से न भेजे जाने के कारण यदि पुनः सी0सी0एल0 निर्गत करने में विलम्ब होता है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। मुख्य अभियन्ता का भी यह दायित्व होगा कि विभागीय योजनाओं की समय से समीक्षा कर समय से प्रतिशत के अनुसार सी0सी0एल0 निर्गत करेंगे।

3- वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड V भाग- 1 के प्राविधानों के सभी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद ही आवश्यकता के अनुसार धनराशि आहरित एवं वितरित की जायेगी।

4- उत्तराखण्ड में लागू अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा तद्विषयक समय-समय पर जारी विभिन्न शारानादेशों के अधीन ही समस्त प्रक्रियायें एवं नियमों का अनुपालन किया जायेगा तथा ऐसे कार्य जो मानक के अनुसार 18 माह में पूर्ण होने चाहिये, ऐसे प्रकरणों में अधिवृद्धि या शेड्यूल रेट्स की दरों में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी।

(हस्ताक्षर)

- 5-- साख रीमा मानक के अनुसार प्रत्येक त्रैमास में निर्गत की जायेगी तथा यदि मानक से अधिक साख रीमा की आवश्यकता हो तो तत्काल शासन से इस संबंध में अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 6-- 15 नवंबर एवं 15 जनवरी को प्रत्येक दशा में excess saving statement निर्धारित प्रपत्र पर प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 7-- न्यायालय की आज्ञाप्तियों के भुगतान मद में भुगतान करने से पूर्व शासन की पूर्वानुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।
- 8-- साख रीमा के आधार पर आवंटित धनराशि का एकमुश्त आवंटन आहरण वितरण अधिकारी/कार्य स्थल पर किया जाये एवं उसका पूर्ण विवरण बी0एम0 के प्रस्तर-17 में भरकर शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 9-- जिन प्रकरणों पर शासन से पूर्वानुमति की आवश्यकता हो उन पर यथाशीघ्र सुस्पष्ट विवरण एवं प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 10-- जिन योजनाओं में केन्द्रांश अवमुक्त होने के बाद धनराशि व्यय करने की व्यवस्था हो उनमें केन्द्रांश अवमुक्त होने के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जायेगा और जिनमें केन्द्र सरकार के द्वारा धनराशि व्यय करने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था हो, उन योजनाओं पर ही अवमुक्त की जा रही धनराशि को आहरित कर व्यय किया जा सकता है।
- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय की अनुदान सं0 22 के संलग्नक 1 में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।
- 11-- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू.ओ.-577/XXVII(2)/2009, दिनांक 05 अक्टूबर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।

संख्या-~~478~~ (1)/111(3)/09-07(सामान्य)/2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबर्नोय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मंडल, पौड़ी/नैनीताल।
- 3- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- मुख्य अभियंता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो0नि0वि0, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 6- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
- 7- नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
- 8- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 9- लोक निर्माण अनुभाग-1/2 उत्तराखण्ड शासन/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रदीप

(महिमा)

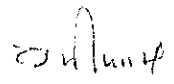
अनु सचिव।

शासनादेश सं०- 478/ 111-(3)/09-07(सामान्य)/09 दिनांक ०५ अक्टूबर, 2009 का संलग्नक
लोक निर्माण विभाग

अनुदान सं०- 22 लेखाशीर्षक-5054 (आयोजनागत)

			(धनराशि हजार में)
क्र.सं.	मद/योजना का नाम /उपमद		अवमुक्त धनराशि
1	2		3
1.	विशेष केन्द्रीय सहायता के कार्य (100 प्रतिशत के०स०)	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04- जिला तथा अन्य सड़के 800- अन्य व्यय 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01- देहरादून रिंग रोड, बगौली एवं गोपेश्वर लिंक रोड श्रीनगर पौड़ी को चौड़ा करना 24- वृहत्त निर्माण कार्य	1,75,00
2.	इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी योजना (100 प्रतिशत के०स०)	04- इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी योजना (100 प्रतिशत के०स०) 24-वृहत्त निर्माण कार्य	4,05,00
	योग:-		5,80,00

(रूपये पांच करोड़ अस्सी लाख मात्र)


(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव।